सतीश कुमार मित्तल जे. के समक्ष

धर्म पाल देशवाल- याचिकाकर्ता

बनाम

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और एक अन्य प्रतिवादी

2009 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 868

4 नवम्बर, 2009

भारत का संविधान1950, अनुच्छेद 226 - याचिकाकर्ता सीपीएफ योजना द्वारा शासित होने का विकल्प चुन रहा है - विश्वविद्यालय सीपीएफ से पेंशन योजना में विकल्प बदलने के अवसर प्रदान करता है - याचिकाकर्ता सेवा से लंबित रहा क्योंकि वह विश्वविद्यालय दिये गये समय के भीतर विकल्प बदलने में असमर्थ रहा दिया गया है और विश्वविद्यालय-—दीवानी न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर विकल्प बदलने के लिए आवेदन करने में विफल रहा है, जो इसे अवैध, प्रारंभिक रूप से अमान्य और शून्य ठहराने के आदेश को रद्द करता है - याचिकाकर्ता को उसके अवैध निष्कासन के कारण ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में विफलता - इसके लिए कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता की बहाली के एक महीने के भीतर किए गए अपने विकल्प को बदलने के अनुरोध को अस्वीकारकरना - केवल इसलिए कि विकल्प में बदलाव से कुछ वित्तीय प्रभाव होंगे, याचिकाकर्ता को उक्त लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है - याचिका को लागत के साथ अनुमति दी गई, उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार पेंशन लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता के सीपीएफ से पेंशन योजना में अपने विकल्प को बदलने के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है कि उन परिपत्रों में दिया गया समय समाप्त हो गया है। जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, उसे उन परिपत्रों के तहत अपना विकल्प बदलने का कोई मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय, वह एक बर्खास्त कर्मचारी होने के नाते, उन परिपत्रों के तहत अपना विकल्प नहीं बदल सकता था। इसलिए, बहाली के तुरंत बाद, आवेदक को उन परिपत्रों के तहत अपने विकल्प को बदलने का अवसर दिया जाना था, जिसे वहन नहीं किया गया है और दूसरी ओर, विकल्प बदलने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता द्वारा विकल्प बदलने से कुछ वित्तीय प्रभाव होंगे, याचिकाकर्ता को उक्त लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से और मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया है और बाद में, जब उसे दीवानी कोर्ट द्वारा बहाल किया गया था, तो उन्होंने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को अपना विकल्प बदलने और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उचित अवसर से वंचित कर दिया है।

(Para 11)

याचिकाकर्ता की ओर से राकेश नागपाल, वकील।

विनोद एस. भारद्वाज, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

<u>निर्णय</u>

सतीश कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति ।

1. याचिकाकर्ता, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की सेवाओं से क्लर्क के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है (प्रतिवादी संख्या 1) मैंने 30

नवम्बर, 2008 को अधिवषता की आयु प्राप्त करने पर . प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 3 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल याचिका दायर की है, जिसके तहत सीपीएफ से पेंशन योजना में विकल्प बदलने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि जब याचिकाकर्ता प्रतिवादी विश्वविद्यालय में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था, तो उसे 18 फरवरी, 1993 को कुछ गलत आचरण के लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के विचार पर निलंबित कर दिया गया था। 8 नवंबर, 1993 को याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र दिया गया, जिसका उसने जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया और विभागीय जांच का आदेश दिया गया। अंत में, दिनांक 30 सितंबर, 1994 के आदेश के तहत , याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने की सजा सुनाई गई थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वैधानिक अपील दायर की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने 19 अप्रैल, 1995 को खारिज कर दिया।

3 याचिकाकर्ता ने सेवा से हटाए जाने के आदेश के साथ-साथ दीवानी मुकदमा दायर कर अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी। सिरसा के दीवानी जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने 7 मार्च, 2002 के अपने फैसले और डिक्री के माध्यम से मुकदमे को आंशिक रूप से डिक्री किया। याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के आदेश को अवैध, अमान्य घोषित किया गया था। उन्हें फिर से नियुक्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन वापस मजदूरी के बिना उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ, याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने अलग-अलग अपील दायर की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरसा की अदालत ने दिनांक 10 जनवरी, 2006 के अपने निर्णय (अनुलग्नक पी-1) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया

और प्रतिवादी विश्वविद्यालय की अपील को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को संशोधित किया गया था और याचिकाकर्ता को उसकी बर्खास्तगी की तारीख से उसकी बहाली की तारीख तक निर्वाह भत्ता, वेतन की बकाया राशि और अन्य सभी परिणामी सेवा लाभों सहित पूर्ण वेतन का हकदार माना गया था। उक्त निर्णय और डिक्री अंतिम हो गई, और दिनांक 21 मार्च, 2006 (अनुबंध पी -2) के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता को सेवा में फिर से शामिल किया गया।

4 उस समय, जब याचिकाकर्ता निलंबित था, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने दिनांक 9 अप्रैल, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से 1 जनवरी, 1992 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पेंशन योजना लागू की। प्रतिवादी विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, जो 1 जनवरी, 1992 को सेवा में थे या 1 जनवरी, 1992 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, को सीपीएफ से पेंशन योजना में अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया गया था। प्रतिवादी विश्वविद्यालय का यह मामला है कि 5 अगस्त, 1993 के अपने विकल्प के तहत याचिकाकर्ता ने सीपीएफ योजना को जारी रखने का विकल्प चुना था। 30 सितंबर, 1994 को याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया।

5 यह स्वीकार किया जाता है कि बाद में, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने दिनांक 10 अप्रैल 1996 के परिपत्र (अनुबंध पी -3) के माध्यम से अपने कर्मचारियों को सीपीएफ से पेंशन योजना में अपना विकल्प बदलने का एक और अवसर दिया। उस समय, याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया था., इसलिए, वह इसका विकल्प नहीं चुन सकता था। हालांकि, कुछ कर्मचारी, जिन्होंने पहले सीपीएफ का विकल्प चुना था, ने पेंशन योजना में अपना विकल्प बदल दिया। इसके अलावा, दिनांक 26 फरवरी, 1999 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को सीपीएफ से पेंशन योजना में अपना विकल्प बदलने का एक और मौका दिया। उस समय भी, याचिकाकर्ता को

सेवा से हटा दिया गया था और वह अपना पद नहीं बदल सकता था। तत्पश्चात्, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 के परिपत्र (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को पुन इसी प्रकार का प्रस्ताव दिया गया। उस समय भी, याचिकाकर्ता सेवा में नहीं था और वह पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुन सकता था। हालांकि, यह निर्विवाद स्थिति है कि इन बाद के अवसरों को देखते हुए, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कई कर्मचारियों ने सीपीएफ से पेंशन योजना में अपना विकल्प बदल दिया है।

6 दीवानी न्यायालय के निर्णय और डिक्री के अनुपालन में 23 मार्च, 2006 को अपनी पुन नियुक्ति के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने 12 अप्रैल, 2006 (अनुलग्नक पी-6) को सीपीएफ से पेंशन योजना में अपने विकल्प को बदलने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 6 मई, 2006 (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से बिना किसी कारण का खुलासा किए याचिकाकर्ता के विकल्प में बदलाव के अनुरोध को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूपी संख्या दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। 2006 का 16418। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता 30 नवंबर, 2008 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। इसके बाद, दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 (अनुलग्नक पी-12) के आदेश के तहत, उक्त याचिका का निपटान इस न्यायालय द्वारा किया गया था कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के लिए एक विस्तृत प्रतिनिधित्व कर सकता है और प्रतिवादियों को अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक मौखिक आदेश पारित करके उस अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 (अनुलग्नक पी-13) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि चूंकि पेफॉनर अवसर प्राप्त होने पर विकल्प बदलने का विकल्प नहीं चुन

सकता था, इसलिए अब इस स्तर पर, विकल्प को बदलने के लिए उसे लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए, यह रिट याचिका।

7. प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित वक्तव्य में यह कहा गया है कि जब प्रतिवादी विश्वविद्यालय में पेंशन योजना शुरू की गई थी- दिनांक 9 अप्रैल, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सीपीएफ योजना या पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 5 अगस्त, 1993 के अपने विकल्प के तहत सीपीएफ योजना द्वारा शासित बने रहने का विकल्प चुना और उसके बाद, जब प्रतिवादी विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को अवसर प्रदान किए गए, तो याचिकाकर्ता ने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना। इसलिए, एक बार याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया विकल्प अंतिम हो जाने के बाद, उसे अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह आगे कहा गया है कि अब, बाद के परिपत्रों के तहत भी विकल्प बदलने का समय समाप्त हो गया है, इसलिए, इस देर से चरण में, याचिकाकर्ता को अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव होंगे।

8. मैंने पक्षकारों के वकील को सुना लिया है।

9. जैसा कि ऊपर बताया गया है, भौतिक तथ्यों को किसी भी पक्ष द्वारा दूषित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता 30 सितंबर, 1994 से 21 मार्च, 2006 तक सेवा से बाहर था, इसलिए वह प्रतिवादी के पास विकल्प बदलने के लिए आवेदन नहीं कर सकता था

विश्वविद्यालय ने 10 अप्रैल, 1996, 26 फरवरी, 1999 और 18 अप्रैल, 2001 को तीन परिपत्र जारी किए जिनमें कर्मचारियों को सीपीएफ से पेंशन योजना में अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ता को सेवा से हटाना दीवानी कोर्ट द्वारा अवैध, शून्य और शून्य माना गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की संबंधित समय पर उपरोक्त तीन परिपत्रों के तहत अपने विकल्प का उपयोग नहीं करने के लिए कोई गलती नहीं थी। जैसे ही उन्हें फिर से नियुक्त किया गया, उसके तुरंत बाद, उन्होंने सीपीएफ से पेंशन योजना में अपना विकल्प बदलने के लिए आवेदन किया। लेकिन उनकी प्रार्थना को उत्तरदाताओं द्वारा बिना किसी औचित्य के अवैध रूप से और मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि 10 अप्रैल, 1996, 26 फरवरी, 1999 और 18 अप्रैल, 2001 के परिपत्रों के तहत, कर्मचारियों को अपने विकल्प प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट समय प्रदान किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने उस समय के भीतर इसके लिए आवेदन नहीं किया था, इसलिए, अब देर से चरण में, उसे अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान भी, वह सेवा से हटाए गए, वह अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, सीपीएफ राशि सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ याचिकाकर्ता के खाते में जमा किए गए हैं। इसलिए, इस देर से चरण में, उन्हें अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने डॉ. एसबी कालीधर बनाम प्रबंधन बोर्ड, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य (2008 का सीडब्ल्यूपी संख्या 2314, 22 अप्रैल, 2009 को फैसला) में अदालत के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह कहा गया था कि एक बार कर्मचारी अपने विकल्प को बदलने का विकल्प नहीं चुनता है। उसे प्रदान किए गए अवसर के बावजूद, बाद में उसे अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11. पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि यह याचिका अनुमति के योग्य है। यह स्वीकार की गई स्थिति है कि 30 सितम्बर, 1994 से 21 मार्च, 2006 तक याचिकाकर्ता नौकरी से बाहर रहा। दीवानी कोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश को अवैध और अमान्य बताते हुए रद्द कर दिया है, और उन्हें पूर्ण वेतन के साथ सेवा में फिर से शामिल करने का आदेश दिया गया था। दीवानी कोर्ट के फैसले और डिक्री के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को सेवा में फिर से शामिल किया गया था। उस समय के दौरान, याचिकाकर्ता नौकरी से बाहर था, प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा तीन परिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें अपने

कर्मचारियों को अपने विकल्प फॉर्म सीपीएफ को पेंशन योजना में बदलने के लिए नए अवसर प्रदान किए गए थे, यह स्वीकार करते हुए कि दो कर्मचारियों ने उक्त अवसरों का लाभ उठाया है और सीपीएफ से पेंशन योजना में अपना विकल्प बदल दिया है। याचिकाकर्ता, उस समय सेवा में नहीं होने के कारण, उन तीन अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं था। उसकी कोई गलती नहीं थी। प्रतिवादियों द्वारा उन्हें अवैध रूप से हटाए जाने के कारण ही वह उन अवसरों का लाभ नहीं उठा सके। प्रतिवादी विश्वविद्यालय के उस अवैध कार्य के लिए, याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादियों को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त तीन परिपत्रों के तहत अपने विकल्प को बदलने के अवसर का लाभ नहीं उठाया। यह एक तथ्य है कि पुन: बयान के एक महीने के भीतर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय को अभ्यावेदन दिया, जिसमें सीपीएफ से पेंशन योजना में अपने विकल्प को बदलने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा उस प्रार्थना को अस्वीकार करना अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ता के उक्त अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है कि उन परिपत्रों में दिया गया समय समाप्त हो गया है। जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, उसे . उन परिपत्रों के तहत अपना विकल्प बदलने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय, वह एक कर्मचारी होने के नाते, उन परिपत्रों के तहत अपना विकल्प नहीं बदल सकता था। इसलिए, पुन: बयान देने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता को उन परिपत्रों के तहत अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया जाना था, जिसे वहन नहीं किया गया है और दूसरी ओर, विकल्प बदलने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता द्वारा विकल्प बदलने से कुछ वित्तीय प्रभाव होंगे, याचिकाकर्ता को उक्त लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से और मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया है और बाद में, जब उसे दीवानी कोर्ट द्वारा फिर से नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को अपना विकल्प बदलने और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उचित अवसर से वंचित कर दिया है। डॉ. एस. बी. कालीधर के मामले (सुप्रा) में दिया गया फैसला, जिस पर प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग है। उस मामले में, उपरोक्त तीन परिपत्रों के तहत याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए तीन अवसरों के बावजूद, कर्मचारी ने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना, लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, उसने एक अभ्यावेदन दिया कि उसे परिपत्रों में से एक के बारे में पता नहीं था, इसलिए, उसे अपना विकल्प बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस निष्कर्ष पर आते हुए कि उन परिपत्रों के व्यापक प्रसार के बावजूद। उस मामले में याचिकाकर्ता ने जानबूझकर

पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना, उसके दावे को खारिज कर दिया गया। इसलिए, उक्त मामले की तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(12) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका को जुर्माने के साथ स्वीकार किया जाता है और दिनांक 3 जनवरी, 2009 (अनुलग्नक पी-14) के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादियों को सीपीएफ से पेंशन योजना में विकल्प बदलने और कानून के अनुसार पेंशन लाभ जारी करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है। सीपीएफ की जमा राशि याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया भुगतान प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित किया जाएगा।

(13) लागत 10,000/- रुपये आंकी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी